डिजिटल पहचान

डॉ सौरभ गर्ग

ऑनलाइन सत्यापन की विशिष्ट डिजिटल पहचान 'आधार' भारत में डिजिटल क्रांति की मुख्य नींव रही है। इस सार्वजनिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) ने एक दशक के समय में ही सरकार द्वारा चलाए जा रहे कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में ज़बरदस्त क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। प्रत्येक नागरिक के लिए 12 अंकों वाली विशिष्ट पहचान (आईडी) संख्या पर आधारित इस प्रणाली से वित्तीय समावेशन, कल्याणकारी सेवाओं तक पहुंच, कर अनुपालन, खुदरा भुगतान और सरकारी सब्सिडी के प्रबंधन आदि में महत्वपूर्ण सुधार आया है। आधार इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्लॉकचेन्स, आईटीओ जैसी नई प्रौद्योगिकियों के समन्वयन से देश के मौजूदा और भावी क़ानूनों की सीमाओं का पालन करते हुए भी बेहतर परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। फ़िनटेक अर्थात् आर्थिक-तकनीकी सेवाओं के विशाल पैमाने पर विस्तार की प्रक्रिया में संभवत: यह 'आधार' व्यवस्था अकेली सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है।

भारत सरकार ने जब 2009 में आधार परियोजना शुरू की थी तो आवश्यक प्रौद्योगिकीय बुनियादी ढांचा बनाना और देश के दूर-दूर तक के क्षेत्रों में रह रहे 130 करोड़ लोगों तक पहुंच पाना एक बहुत कठिन चुनौती लग रहा था क्योंकि विशिष्ट आधार संख्या निर्धारित करने में किसी भी तरह की पुनरावृत्ति नहीं होने देना नितांत अनिवार्य शर्त थी।

2014 में यह परियोजना जनधन पहल के साथ जोड़ दी गई जो देश में बड़ी संख्या में बैंकिंग सुविधाओं से वंचित लोगों तक ये सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। जनधन योजना के तहत खोले गए खातों को मोबाइल नंबरों और आधार नंबरों से जोड़कर जनधन-आधार-मोबाइल यानी जेएएम का त्रिकोणीय प्रावधान प्रारंभ किया गया। इस समय देश में 80 प्रतिशत लोगों का बैंक खाता है जबकि यह कार्यक्रम शुरू होने के समय सिर्फ 40 प्रतिशत लोगों के ही बैंक खाते थे। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान

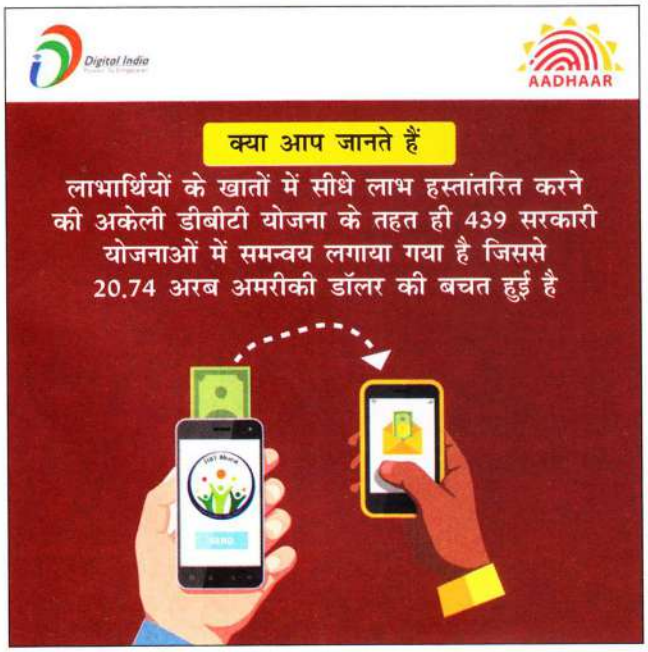

लेखक यूआईडीएआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। ईमेल: ceo@uidai.gov.in

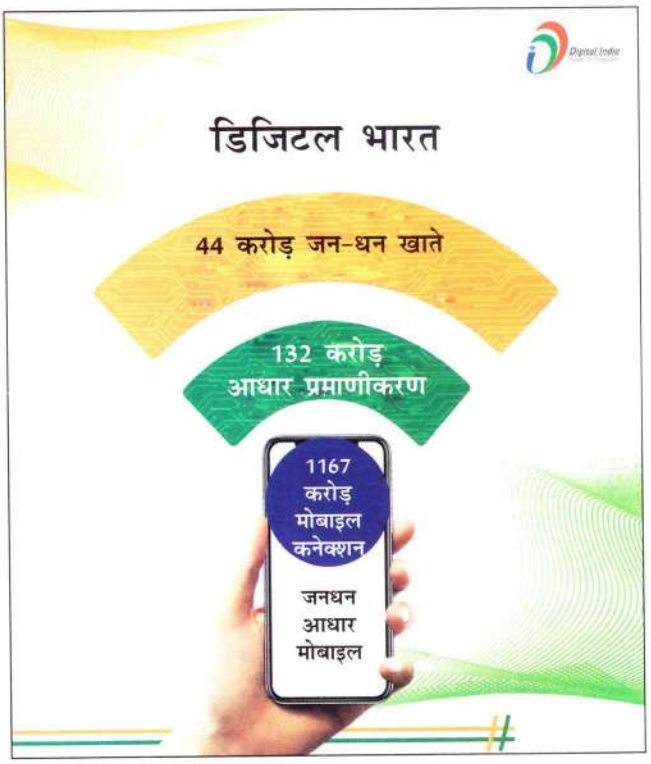

निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधार भुगतान सेतु (एपीबी) अब देश की सामाजिक सुरक्षा और नक़दी हस्तांतरण कार्यक्रम में तेज़ी लाने वाला सबसे प्रमुख माध्यम है। इस समय केंद्र सरकार 314 कार्यक्रमों/योजनाओं के लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि भेजने के लिए एपीबी-चालित व्यवस्था अपना रही है। राज्य सरकारों के 450 अन्य कार्यक्रमों के तहत लाभार्थियों को सीधे खाते में पैसा भेजने में डिजिटल व्यवस्था अपनाई जा रही है। मैककिंसे ग्लोबल इंस्टीट्यूट ने मार्च, 2014 में जारी रिपोर्ट 'डिजिटल इंडिया' में कहा था कि ''भारत में तेज़ी से डिजिटीकरण लागू किए जाने की प्रक्रिया को तेज़ करने में सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आधार व्यवस्था का व्यापक विस्तार करने में 'आधार' ने बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान किया है।''

वित्तीय सेवाओं में विस्तार लाने की क्षमता

आधार अपनी विशेष खूबियों के कारण पहचान का बेहतर माध्यम (दस्तावेज़) बनकर उभरा है।

- 'आधार में अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)' का पूरी तरह पालन किया जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक का कहना है कि यदि बैंक खाता खोलते समय प्रस्तुत किए जाने वाले आधिकारिक रूप से मान्य दस्तावेज़ (कार्ड) में आवश्यक व्यक्तिगत विवरण और निवास का पता अंकित है तो फिर कोई अन्य सबूत पेश करने की ज़रूरत नहीं है। आधार में ये दोनों विवरण शामिल हैं और तभी यह (छोटे खाते खोलने के लिए) अपने आप में पर्याप्त वैध दस्तावेज़ हैं।
- इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी (ई-केवाईसी): आधार प्लेटफॉर्म ई-केवाईसी सेवा उपलब्ध कराता है। देशवासियों की सहमति से उनका भौगोलिक विवरण और फोटो डिजिटल माध्यम से सेवा प्रदाता के साथ शेयर किया जाता है। इस विधि से ग्राहक अधिग्रहण (उपलब्धता) प्रक्रिया बेहद सरल हो जाती है।
- आधार सत्यापन का अकेला पर्याप्त प्रमाण है - आधार के ज़रिए सत्यापन करने की सरलता को देख-समझकर बैंक, बीमा कंपनियां, शेयर दलाली में लगी कंपनियां और सरकारी प्रतिभूतियां भी नए ग्राहकों को आकर्षित करने में इस प्रक्रिया को अपनाने में लगी हैं जिससे देशवासियों को डिजिटल सेवाओं के लाभ प्राप्त करने में मदद मिल रही है। नागरिक इस योजना में शामिल होने के बाद सत्यापन के लिए अपना आधार नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं और जितनी बार चाहें इसे अपनी पहचान के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। आधार उपलब्ध कराने के बाद नागरिकों को ये सेवाएं, लाभ और सब्सिडी पाने के वास्ते पहचान के लिए हर बार कोई अन्य प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

भारत का डिजिटल उपभोक्ता आधार विश्व में दूसरा सबसे बड़ा है और सभी वर्गों के लोग प्रौद्योगिकी से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ महसूस कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था के मुख्य पहलुओं तथा निजी क्षेत्र में नवाचार और निवेश के लिए इंटरनेट एक्सेस (पहुंच) और प्रयोग बढ़ने से ही भारत में डिजिटल प्रक्रिया अपनाने की गति इतनी तेज़ करने में सफलता प्राप्त हुई है। सरकार ने इस प्रक्रिया को बढ़ावा देने और इसमें तेज़ी लाने के उद्देश्य से मज़बूत राष्ट्रीय डिजिटल आधार-सार्वजनिक प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है और इसके लिए अनेक डिजिटल एप्लीकेशंस और सेवाएं शुरू की हैं।

भारत में वित्तीय डिजिटल व्यवस्था की नींव को मज़बूत बनाने में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) और भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम)/भारत क्विक रेस्पांस (क्यूआर) कोड, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट ऐक्सेस और रिट्रीवल के लिए डिजिलॉकर, ग्राहकों की पहचान की डिजिटल पुष्टि करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक 'नो योर कस्टमर' (ई-केवाईसी) व्यवस्था, ई-हस्ताक्षर, एपीबी, आधार एनेबल्ड भुगतान प्रणाली (एईपीएस) और भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस)- जैसे विभिन्न एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस-एपीआई सैट की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भविष्य में भी डिजिटल माध्यम से पहचान पुष्टि प्रणालियों की व्यापक रेंज़ विकसित होती रहेंगी जिनमें नागरिकों की निजता पूरी तरह से सुरक्षित रहेगी। भारत सरकार ने 2014 में प्रधानमंत्री जन-धन योजना आरंभ करके राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन अभियान को सुचारू ढंग से आगे बढ़ाया और इस योजना के अंतर्गत आधार कार्ड से पहचान की पुष्टि करके लाखों लोगों के बैंक खाते खोले गए। 26 जनवरी, 2022 तक 44 करोड़ 58 लाख जनधन बैंक खाते खोले जा चुके थे। अब भारतीयों के जीवन में डिजिटल समाधान

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा विकसित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आधार भुगतान सेतु (एपीबी) अब देश की सामाजिक सुरक्षा और नक़दी हस्तांतरण कार्यक्रमों में तेज़ी लाने वाला सबसे प्रमुख माध्यम है।

बहुत अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं।

वैश्विक बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम 'आधार' के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द 'इंडिया स्टैक' और इससे संबद्ध खुले एपीआई का पूरा सैट भारत में डिजिटल नींव को मज़बूत करने और देश के डिजिटल विकास में ज़बरदस्त भूमिका निभा रहे हैं। मूल सिद्धांतों के आधार पर यह सिद्ध हो गया है कि डिजिटल सेवाओं से बड़ा लाभ यह है कि स्वयं मौजूद हुए बिना और कहीं से भी उपस्थिति का प्रमाण देने की इस व्यवस्था में कोई काग़ज़ी कार्रवाई नहीं करनी पड़ती या फिर डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित होने के कारण नक़दी लेनदेन की ज़रूरत नहीं पड़ती और इस प्रकार सही मायनों में वैश्विक डिजिटल भुगतान किए जा सकते हैं और डिजिटल पहुंच प्राप्त की जा सकती है; या 'सहमति के आधार पर' या डाटा प्रमाणीकरण के लिए खाताधारक तक सुरक्षित पहुंच प्राप्त की जा सकती है। वैश्विक प्रौद्योगिकी प्रक्रियाओं के विकास से निजी क्षेत्र का निवेश बहुत तेज़ी से बढ़ा है और नवाचार भी व्यापक रूप से अपनाए जा रहे हैं जिससे भारत में डिजिटल उपभोक्ता क्षेत्र का ज़बरदस्त विस्तार हुआ है।

वैश्विक बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम आधार के संदर्भ में प्रयोग किया जाने वाला शब्द 'इंडिया स्टैक' और इससे संबद्ध खुले एपीआई के पूरे सैट ने भारत में डिजिटल कार्यक्रम की नींव को मज़बूत करने और देश के डिजिटल विकास में ज़बरदस्त भूमिका निभाई है।

फ़िनटेक यानी आर्थिक-तकनीकी नवाचार क्षेत्र का बहुत तेज़ी से विस्तार हुआ है। एक सर्वेक्षण के अनुसार फ़िनटेक आंदोलन में भारत को विश्व में दूसरे स्थान पर रखा गया है और बताया गया है कि देश के 76 प्रतिशत उपभोक्ताओं ने माना है कि वे वित्तीय सेवाओं के लिए कम से कम एक गैर-परंपरागत फर्म चला रहे हैं। सरकार ने नीति प्रयोगशाला में, नियामक सैंडबॉक्सों, इनक्यूबेशन सेंटरों और फ़िनटेक तथा आईओटी आधारित नई एप्लीकेशंस के द्वारा निजी क्षेत्र में नवाचार के लिए अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है। निजी क्षेत्र में नवाचार प्रक्रिया को सक्रिय करना डिजिटल भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत महत्वपूर्ण है।

इस फ़िनटेक लहर का लाभ लेने के लिए बैंक फ़िनटेक स्टार्टअप कंपनियों को सहायता और सहयोग दे रहे हैं। भारत के डिफ्रेंशियल बैंकों (भुगतान और छोटे वित्त बैंकों) ने भी उन वित्तीय सेवाओं के समूचे समूह में बड़े डिजिटल नवाचार अपनाए हैं जो बैंकिंग नियामक भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं तथा इस उद्देश्य के लिए वित्तीय क्षेत्र में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपनाने का संभावित प्रारूप तैयार किया जा चुका है।

आधार-प्रणाली वाली माइक्रो एटीएम व्यवस्था अच्छी तरह प्रयोगा की जा रही है और इस प्रणाली में कई अन्य एप्लीकेशन विकसित की जा सकती हैं। यूआईडीएआई भी नागरिकों को बीमा और निवेश की अन्य नई सेवाएं उपलब्ध कराने के तरीक़े खोजने में लगा है।

यूपीआई के माध्यम से लेनदेन की संख्या बढ़कर इस वर्ष जनवरी में 460 करोड़ को पार कर चुकी थी। भुगतान करने, शॉपिंग में और ई-कॉमर्स उद्योगों की दृष्टि से यह बढ़ोतरी बहुत ज्यादा है। यह भी एकदम स्पष्ट हो गया है कि इस समूची प्रक्रिया में डिजिटल पहचान व्यवस्था का भी बहुत बड़ा योगदान है। इंडिया स्टैक और इसके इस्तेमाल से जुड़े टेक्नोलॉजी विकास इस क्षेत्र में ज़बरदस्त सफलता प्राप्त करने में सहायक रहे हैं। टेक्नोलॉजी में निरंतर विकास होता रहना चाहिए। आधार का बुनियादी ढांचा भी इससे अलग नहीं है और कई प्रकार से इसका भी विकास हो रहा है। देशवासियों को सीधे उनके खातों में भुगतान पहुंचने की व्यवस्था से यह अच्छी तरह सिद्ध हो चुका है।

डिजिटल पहचान के तौर पर आधार से हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से कई और लाभ प्राप्त करने की आशा रखते हैं। यूआईडीएआई टीम इस चुनौती के लिए पूरी तरह तैयार है। एआई/एमएल और अनुसंधान तथा विकास में लगी टीमें मौजूदा चुनौती से निपटने में बहुत सही काम कर रही हैं। नए आधार कार्ड में एक आधुनिकतम और पूर्णत: सुरक्षित क्यूआर कोड है जिसमें फोटो भी लगा है। क्यूआरकोड जैसे आधार की पुष्टि के ऑफलाइन प्रमाणन जैसे तरीकों से विभिन्न उद्देश्यों के लिए लोगों

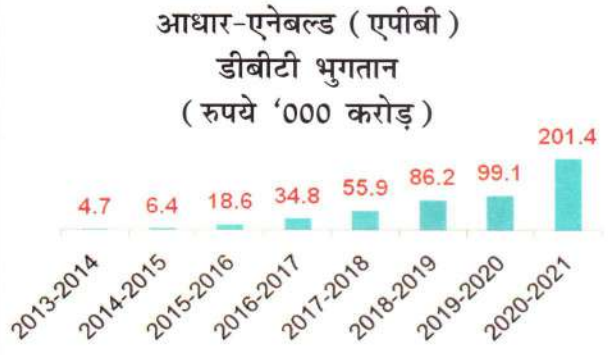

850 करोड़ लेनदेन और 5.75 लाख करोड़ रु नक़द लाभ
120 करोड़ खाते आधार के माध्यम से खोले
75 करोड़ आधार से जुड़े विशिष्ट खाते

1200 करोड़ एईपीएस लेनदेन
40 करोड़ सफल लेनदेन प्रतिमाह
50 लाख माइक्रो एटीएम : 35 लाख लेनदेन प्रति माह

की पहचान की पुष्टि के आसान तरीक़े भी उपलब्ध होते हैं।

हमारा मानना है कि ब्लॉकचेन्स, आईओटी जैसी नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल करके आधार इंफ्रास्ट्रक्चर देश के मौजूदा और भावी क़ानूनी सीमा के दायरे में रहकर भी सभी उपयोगी सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है। फिर भी, यह समझना-जानना बहुत ज़रूरी है कि इस डाटा को लोगों के लाभ के लिए और किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। फ़िनटेक सेवाओं के व्यापक विस्तार में आधार प्रणाली भारत में सबसे विश्वस्त अकेली व्यवस्था है।

एईपीएस के माध्यम से नक़दी निकासी, बैलेंस चैक करने जैसी बैंकिंग सेवाएं लोगों को घर बैठे मिल रही हैं। यह व्यवस्था गांव-देहात के लोगों के लिए और खासकर वैश्विक महामारी के दौर में बड़ा वरदान साबित हुई है। चूंकि 'फ़िनटेक' इस समय वित्तीय क्षेत्र में बहुत बड़ा अहम बन चुका है तो ऐसे में इसके अनुरूप पहचान प्रणाली विकसित करना भी न केवल मददगार है बल्कि आवश्यक हो गया है।

अभी तो यह डिजिटल क्रांति की शुरुआत है और 2022 में तथा आगे चलकर भी बहुत सी नई संभावनाएं हैं। चेहरे की पहचान की पुष्टि और जीवित होने/न होने के प्रमाण जैसे पहलू वीडियो केवाईसी की असल ताक़त या कहें कि रीढ़ हैं और इन सुविधाओं को अब अधिकांश फ़िनटेक/बीएफएसआई उद्योग ग्राहकों की पहचान का सबसे सरल और प्रमाणिक तरीक़ा मानने लगे हैं। यूआईडीएआई भी इसे पहचान फेस की चौथी व्यवस्था के तौर पर लागू करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल, यूआईडीएआई ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड), फिंगरप्रिंट अर्थात् उंगलियों के निशान और आइरिस (आंख की पुतली) के माध्यम से ग्राहकों की पहचान की पुष्टि करता है।

अभी तो यह डिजिटल क्रांति की शुरुआत है और 2022 में तथा आगे चलकर भी बहुत सी नई संभावनाएं हैं। चेहरे की पहचान की पुष्टि और जीवित होने/न होने के प्रमाण जैसे पहलू वीडियो केवाईसी की असल ताक़त या कहें कि रीढ़ हैं और इन सुविधाओं को अब अधिकांश फ़िनटेक/बीएफएसआई उद्योग ग्राहकों की पहचान का सबसे सरल और प्रामाणिक तरीक़ा मानने लगे हैं।

माना जा रहा है कि 2022 में अधिकांश फ़िनटेक/बीएफएसआई उद्योग इन डिजिटल पहचान सेवाओं को अपना लेंगे जिससे वे ग्राहकों को कम खर्चे पर और तुरंत सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

यूआईडीएआई कई अन्य टेक्नोलॉजिकल मोर्चों पर भी काम कर रहा है और देश में नई और तीव्र गति वाली अर्थव्यवस्था विकसित करने की दिशा में औद्योगिक भगीदारों के साथ कदम मिलाकर नए परिवर्तनों के अनुरूप ढलने की चुनौती से निपट सकेगा। ■